अनुसूचित जातियों के बेरोजगार पायलट

196. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या **पर्यटन और** नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स में ग्रेड एक, दो और तीन के पदों में अब तक आरक्षित कोटे के अनुसार अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की भर्ती नहीं की गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनेक हरिजन/अनुसूचित जाति के पायलट, जिनके प्रशिक्षण पर सरकार ने भारी व्यय किया है, अभी भी बेरोजगार हैं ; और

(ग) इन मामलों में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे. बी. पटनायक) : (क) जी, नहीं। एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइस दोनों ही ने ग्रेड I, II तथा III में, इन वर्गों की रिक्तियों के आरक्षण संबंधित सरकारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की, जहां तक उपयुक्त एवं योग्य व्यक्ति उपलब्ध हो सके हैं, भर्ती की है।

(ख) और (ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कुछ ऐसे बेरोजगार विमानचालक हैं जिन्हे इंडियन एयरलाइंस द्वारा चयन के समय एक मौका दिया गया था परन्तु वे उपयुक्त नहीं पाये गये, वस्तुतः नियमित भर्ती के अलावा, इंडियन एयरलाइंस ने 1977 में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये एक अलग से भी चयन किया था और जो उम्मीदवार उपयुक्त पाये गये, उन्हें शिक्षण पर ले लिया गया था। इंडियन एयरलाइंस तथा सरकार का यह सतत प्रयत्न रहता है कि इस बात को सुनिश्चित किया जाये कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रिक्तियों को इन वर्गों के ही उपयुक्त उम्मीदवारों द्वारा भरा जाये।

दिल्ली में सस्ते होटल तथा पर्यटक दुकानें

197. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या **पर्यटन तथा नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पर्यटन विभाग द्वारा बड़े होटलों के बजाय दिल्ली में तथा देश के अन्य स्थानों पर छोटे तथा सस्ते होटल तथा पर्यटक दुकाने खोलने की कोई योजना बनाई जा रही है ?

पर्यटन तथा नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) जी, हां। अधिक लागत वाले, मंहगे होटलों के बजाय, जिनके लिये कि अधिक परिव्यय की आवश्यकता होती है, पर्यटन योजना में उपलब्ध सीमित संसाधनों के अन्तर्गत कम लागत वाले, सस्ते होटल उपलब्ध कराये जाने के संबंध में लिये गये निर्णय के अनुसरण में और साथ ही स्वदेशी पर्यटकों और अन्तर्राष्ट्रीय मितव्ययी पर्यटकों की स्वच्छ, आरामदेह और सस्ते आवास की जरूरत को पूरा करने के लिये नई दिल्ली में एक 1250 बैड वाले जनता होटल (अशोक यात्री निवास) का निर्माण किया जा रहा है। पंचवर्षीय योजना 1978–83 के अन्तर्गत बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के महानगरों में इसी प्रकार की यूनिटों का निर्माण करने का कार्यक्रम है। अन्य महत्वपूर्ण केन्द्रों पर, जिनका निर्धारण एक सर्वेक्षण कराने के उपरान्त किया जायेगा, अपेक्षाकृत छोटे-छोटे यूनिटों की स्थापना की जायेगी, बशर्ते निधियां उपलब्ध हों। राज्य सरकारों और गैर-सरकारी उद्यमियों को कम कीमत वाले होटलों की स्थापना करने के लिये प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा। इस उद्देश्य के लिये उनके अनुरोध पर उन्हें डिजाइन भी उपलब्ध कराये जायेंगे।

दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली

198. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन को दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने में पूरी सफलता नहीं मिल पाई ;

(ख) क्या प्रशासन द्वारा बार-बार घोषनायें किये जाने के बावजूद उचित दर की दुकानों के माध्यम से साबुन का वितरण बिल्कुल नहीं हुआ और कपड़े तथा कापियों का वितरण भी नगण्य ही रहा है ; और

(ग) दिल्ली में सार्वजनिक प्रणाली में व्यापक सुधार करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और इस्पात तथा खान मंत्री (श्री प्रचय मुखर्जी) (क) से (ग) : दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में इस समय कुल 2,160 उचित दर की दुकाने हैं। उचित दर की दुकानों के माध्यम से लगभग 11 लाख खाद्य कार्डधारकों को गेहूं, चावल, चीनी, आटा, आर० बी० डी० ताड़ का तेल, रेपसीड तेल और कापियों जैसी कुछ चुनी आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है। उचित दर की दुकानों के अलावा, 1148 खुदरा डिपुओं के माध्यम से मिट्टी के तेल और 1638 डिपुओं के जरिये कोयले का वितरण किया जा रहा है। 800 रु० प्रतिमाह से कम मासिक आय वाले खाद्य कार्डधारियों को 244 सहकारी समितियों के माध्यम से कंट्रोल के कपड़े का वितरण किया जा रहा है। यद्यपि, कापियों और कंट्रोल

के कपड़े का वितरण कार्य कुल मिलाकर संतोषजनक रहा है, तथापि टाटा आयल मिल्स कम्पनी में लम्बी हड़ताल के कारण नहाने के साबुन के वितरण पर असर पड़ा है। यह कंपनी दिल्ली में उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिये 'क्रेसिल' ब्राड़ नहाने के साबुन की सप्लाई कर रही थी। दिल्ली के केन्द्र शासित क्षेत्र और देश के अन्य राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समय-समय पर पुनरीक्षा की जा रही है और चुनी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई तथा वितरण के प्रबंधों को कारगर बनाने के लिये समय-समय पर कदम उठाये गये हैं।

Working of Life Insurance Corporation

199. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the progress made by the Committee appointed by the Government of India to review the working of Life Insurance Corporation; and

(b) when the Committee is likely to submit its report to Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAGANNATH PAHADIA): (a) and (b). The continuance of Committee itself is under the consideration of Government.

समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

200. श्री **मूल चन्द डागा**: क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है अथवा पहले ही कोई ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों को उचित मुल्यों पर चीनी, मिट्टी का तेल, खाद्य पदार्थ आसानी से उपलब्ध हों; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी कोई योजना बनायगी और यदि हां, तो कब तक और इसे कार्यान्वित करने में कितना समय लगेगा?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और इस्पात तथा खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) तथा (ख). अनाज, चीनी, मिट्टी का तेल आदि जैसी कुछ चुनी वस्तुओं का नियत मूल्यों पर वितरण करने की योजना पहले से ही लागू है, जो समाज के पिछड़े व कमजोर वर्गों, सहित समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करती है।

वर्ष 1977, 1978 और 1979 के दौरान विदेशी पर्यटकों से हुई आय

201. श्री **मूल चन्द डागा**: क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1977, 1978 और 1979 के दौरान क्रमशः कितने पर्यटक भारत में आये और उसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी आय हुई थी; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पर्यटकों ने कौन सी प्रमुख कठिनाईयों की ओर पर्यटन विभाग का ध्यान दिलाया और उनको दूर करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक): (क) भारत में 1977, 1978 और 1979 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमनों की संख्या क्रमशः 6,40,422, 7,47,995 और 7,64,781 थी।

इसी अवधि के दौरान देश द्वारा क्रमशः 283 करोड़ रुपये, 330 करोड़ रूपये और 338 करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित करने का अनुमान है।

(ख) जो प्रमुख कठिनाइयां पर्यटन विभाग के ध्यान में लाई गई हैं, वे ये हैं (i) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भीड़-भाड़ जिसके कारण पर्यटकों की तत्काल निकासी में विलम्ब होता है; (ii) इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा स्वदेशी सेक्टरों पर बुकिंग की समय पर पुष्टि करने में असमर्थता और अपनी उड़ान सारणियों (फ्लाइट शैड्युल) में बार-बार परिवर्तन करना, जिसके कारण यात्रा कार्यक्रमों में गड़बड़ी होती है; (iii) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्वीकृत मानकों के होटल आवास की कमी; और (iv) स्थानीय दृश्यावलोकन है और एक मुश्त दौरों के लिये आरामदेह तथा शीघ्रगामी स्थल परिवहन की कमी, जिसमें कारें/कोंचे शामिल हैं।

इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार द्वारा जो उपाय किये जा रहे है, वे ये हैं— (i). बम्बई हवाई अड्डे पर एक नई टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है और दिल्ली हवाई अड्डे के मामले में इसी प्रकार का एक प्रस्ताव सक्रिय रुप से सरकार